Title: Discussion on the point arising out of the answer given by the Minister for Agriculture on 06.12.2004 to Starred Question No. 64 regarding drought affected areas.

17.45 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Drought Affected States

MR. SPEAKER: Now, we take up item no. 18 − Half-an-Hour Discussion.

Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 06-12-04 को प्रश्न संख्या 64 के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि मानसून में ज्यादा देरी हो जाने से कई राज्यों में गंभीर सूखे की आशंका पैदा हो गई थी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ-साथ रोजगार के साथ भी खेती का सीधा संबंध है चाहे वह किसानों के लिए हो या खेतिहर मजदूरों के लिए हो। लेकिन हमारे देश की एक विडम्बना यह है कि प्रत्येक वर्ष अतिवृष्टि के कारण बाढ़ और अनावृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति देश के कई राज्यों में पैदा होती है। लेकिन आज तक कोई सार्थक प्रयास इस समस्या के निदान के लिए नहीं किया गया।

इस वर्ष भी देश में औसतन मानसून की जो वर्षा हुई है, उससे औसतन 13 प्रतिशत कम वर्षा पूरे देश में हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन इसी प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गई है कि अगस्त महीने में मानसून के आ जाने पर कई राज्यों की स्थिति में काफी सुधार आ गया है। लेकिन इस सबके बावजूद जो सबसे बड़ा राज्य बिहार है, वहां मानसून के कारण कोई सुधार नहीं हुआ है। हम इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जबकि पूरे देश में औसतन 13 प्रतिशत कम वर्षा हुई। बिहार में 60 से 70 प्रतिशत कम वर्षा मानसून में हुई जबकि पूरे देश का जो क्षेत्रफल है, उसका 2.8 प्रतिशत बिहार में है और लगभग 8.1 प्रतिशत वहां की आबादी है। आबादी के हिसाब से यदि हम जोड़ें तो 880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. बोझ पड़ता है लेकिन वहां पूरे राज्य में आज स्थिति यह है कि जो आधा उत्तर बिहार है, गंगा के उत्तर का जो भाग है, वह पहले ही बाढ़ की चपेट में है और गंगा के दक्षिण का जो भाग है, वह पूरे सूखे की चपेट आ गया है। जब बंटवारे से पहले संयुक्त बिहार था तो संसाधन की कमी नहीं थी लेकिन बिहार के विभाजन के बाद आज पूरा बिहार कृषि पर आधारित है। वहां कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। वहां सारे उद्योग बंद हैं। पूरे बिहार में उद्योग के नाम पर एक बरौन रिफाइनरी इंडियन ऑयल की चल रही है। उसके अलावा वहां कोई उद्योग नहीं है। इसलिए आज वहां संसाधन का अभाव है और बिहार के लोग कृषि पर आधारित हैं। लेकिन आज इस मानसून के कारण पूरे राज्य की खेती प्रभावित हो गई है। धान की फसल खेतों में लगाई गई। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

किसी तरह किसानों ने डीजल पम्प से धान लगाने का काम किया लेकिन पूरी धान की फसल चौपट हो गई क्योंकि वर्षा बहुत कम हुई। बिहार में सबसे बड़ा जो ताल इलाका है, वह दलहन उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसे ताल इसलिए कहा जाता है कि बरसात ऋतु में वहां पूरे तालाब की स्थिति हो जाती है। वर्षा ऋतु के बाद जब पानी निकलता है तो जमीन की नमी के आधार पर दलहन की बुवाई होती है। लेकिन इस बार पूरे दलहन के क्षेत्र में एक इंच पानी का प्रवेश नहीं हुआ। गांव के बूढ़े-बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में कोई ऐसा वर्ष नहीं देखा जब इस क्षेत्र में पानी नहीं आया हो। वहां के किसानों के लिए आज भुखमरी की स्थिति है।

इन सबके अलावा वहां पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। चूंकि बारिश नहीं होने के कारण, वहां का जलस्तर दस सेंटीमीटर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है। इस कारण वहां पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन दो महीनों के बाद स्थिति और भी बदतर होने वाली है। इस सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि कई राज्यों में टीम भेजने की बात की जा रही है। लेकिन बिहार में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। बिहार में आबंटित और मांग की बात कही गई है, वह भी स्पष्ट नहीं है कि वह मागं बाढ़ के लिए की गई थी या सूखे से निपटने के लिए की गई थी। आज बिहार सरकार के कुप्रबंधन की वजह से वहां स्थिति दयनीय हो गई है। हालांकि कृषि और जल राज्य सरकार का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बिहार की राज्य सरकार प्रबंधन में विश्वास नहीं करती, कुप्रबंधन में करती है। पूरे बिहार की स्थिति भयावह हो गई है। आने वाले समय में और भी भयावह होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वे बताएं कि बिहार सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कितनी मांग की है और क्या कोई कार्य योजना वहां से बनाकर यहां भेजी गई है या नहीं ? सरकार द्वारा सूखे से निपटने के लिए अब तक पैसे का जो आबंटन और खाद्यान्न रिलीज किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह बाढ़ से निपटने के लिए है या सूखे से निपटने के लिए है ? अगर दोनों से निपटने के लिए है तो उसमें से सूखे के लिए कितनी राशि बिहार की सरकार को आबंटित की गई है ? इसके अलावा आने वाले दिनों में जो भयावह स्थिति वहां पैदा होने वाली है, उसके लिए रोजगार पैदा करने वाली योजनाएं, फूड फार वर्क जैसी व्यापक योजनाएं चलाई जाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले। सूखे से राहत देने वाली जो योजनाएं वहां चलाई जाएं, उनकी निगरानी यहां से की जाए, क्योंकि वहां की राज्य सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। उसका तो टोटल कुप्रबंधन है, टोटल अनार्की है। वहां की राज्य सरकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छाशक्ति नहीं है। इसलिए मैं आपके

माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार यहां से इन सारे कार्यक्रमों के लिए यहां से विशेष मानेटरिंग की व्यवस्था करें।

MR. SPEAKER: Thank you. I wish to compliment you. It was very well put.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I would like to put two questions.

MR. SPEAKER: You cannot put. This is not the way to function. There is some thing called 'rules'. For your kind information, the Members, who have previously intimated the Speaker, may ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact. I will call all the four hon. Members whose names have become successful, as you all know, in the ballot.

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, the Government has selected about 150 districts under the Food-for-Work Programme. But there are places where there were no rains continuously for seven years. How is the Government planning to help those places which are not included in the 150 districts?

MR. SPEAKER: Thank you.

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह भी मैंने आपकी इजाजत से इस्से सम्बन्धित मामला विशे उल्लेख के जरिए उठाया था। बिहार में कुछ इलाकों की स्थिति सूखे से बहुत भयंकर है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जल का स्तर भी नीचे चला गया है। इस कारण अकेले नालन्दा जिले में मैंने उस दिन भी उल्लेख किया था कि छः लोगों की भूख से मौत हुई है। वे लोग मुख्यतः दलित वर्ग से आते थे और खेतीहर मजदूर थे। उन सबका नाम लेकर मैंने यहां उल्लेख किया था। मुझे दुःख होता है कि जब मैं वीकएंड की छुट्टियों में अपने संसदीय क्षेत्र गया तो मालूम हुआ कि वहां मरने वालों की संख्या कम से कम 12 हो गई है। स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं। एक महीना पहले मैंने इनसे अपने संसदीय क्षेत्र से दूरभाष पर इस बात का उल्लेख किया था कि वहां पर बुरी हालत है। मैंने वहां के अधिकारियों से भी बात की कि कोई न कोई योजना चलाई जाए ताकि वहां के गरीब खेतीहर मजदूरों को काम मिल सके।

सब लोग खेती पर निर्भर करते हैं और अगर वहां खेती नहीं हो रही है तो लोगों को काम नहीं है और अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोगों को खाने का इंतजाम नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करके कोई काम की योजना चलानी चाहिए और जैसा मैंने उल्लेख किया था कि वहां 12 राज्यों में सूखा पड़ा था और एनडीए की सरकार उस वक्त थी। जिस राज्य ने अनाज मांगा, धन मांगा वह दिया गया। आज कुछ इलाकों में सूखा है। मैं अनुरोध करुंगा कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में जिन जिलों को शामिल नहीं किया गया है, आप उनको शामिल कीजिए।

दूसरे, काम के लिए वहां और योजनाओं को चलाइये और यह जो परिस्थिति पैदा हुई है इसको एक अवसर में आप तब्दील कर सकते हैं। जितने भी हमारे मिट्टी संबंधी काम हैं, उनको किया जा सकता है। सिंचाई के स्रोतों को बनाया जा सकता है। अभी माननीय सदस्य ने टाल क्षेत्र का उल्लेख किया। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि 1 लाख 9 हजार हैक्टेयर जमीन उसमें है और वहां दलहन की खेती होती है। हमने पहले कभी नहीं देखा कि उसमें पानी न आया हो। यह पहली बार हुआ है कि टाल क्षेत्र में, जहां रबी की अच्छी फसल होती थी, वहां जंगल उग आये हैं। वहां बहुत बुरा हाल है और पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है, मवेशियों के लिए चारे का संकट होने जा रहा है। डीजल के दाम बढ़ गये हैं और चारों तरफ हाहाकार है। माननीय देवेन्द्र यादव जी को हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ लगे, लेकिन मानवीय पक्ष की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वहां की सरकार और सरकारी पार्टी मजदूर किसान रैली आयोजित कर रही है। जो पैसा आप रैली में लगा रहे हैं अगर उसे वहां खर्च कर देंते, तो वहां कोई भूख से नहीं मरता। आप उनका वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन वे मर रहे हैं, इसकी चिंता आपको नहीं है। कोई वहां नहीं पहुंचता है, वहां बहुत बुरा हाल है। माननीय कृषि मंत्री जी पहले बैठे हुए थे अब चले गये हैं। अगर वे होते तो मैं उनसे अनुरोध करता कि कम से कम वे एक बार वहां चलें और चलकर देखें कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है या असत्य है, आप स्वयं चलकर देख लें। आपने इसमें आधे घंटे की चर्चा मंजूर की है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करुंगा कि माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी बिहार चलें और उन सूखा-प्रभावित क्षेत्रों को देखें। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं और मैं स्वयं राजस्थान गया था। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि समय निकालकर वे वहां तत्काल जाएं और वहां की परिस्थिति का आकलन करके जो मदद देनी हो वह करें। वहां अगर कोई काम नहीं किया जा रहा है तो उसका रास्ता निकालें कि काम हो। मेरी दूसरी स्पेसिफिक मांग है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो भारत सरकार ने लॉच किया है, उसमें नालंदा जिले को शामिल किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, सूखा प्रभावित राज्य की चर्चा यहां हो रही है, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत के देहातों में 80 करोड़ की आबादी रहती है और ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 18 करोड़ लोग रहते हैं। यह बात सत्य है कि सरकार ने अपना पल्ला इसलिए झाड़ लिया कि अनियमित वर्षा होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई, जिसे हम भी स्वीकार करते हैं। आदरणीय नीतीश जी ने जैसा बताया कि भूख से लोग मर रहे हैं। सरकार के पास बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे राहत पहुंचाकर हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों को बचा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों का सर्वे कृषि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया है कि कितने हैक्टेयर भूमि पर असिंचित और सूखे की स्थिति से वहां पर लोग प्रभावित हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां पर आप सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको लागू करवाएं। रोजगार न मिलने के कारण जो सीमांत कृाक हैं जिनके पास डेढ़ बीघे, दो बीघे जमीन है, वे भुखमरी के कगार पर हैं।

18.00 hrs.

उनका पलायन गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण शहरों में भी रोजगार की समस्या बढ़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे खाद्यान्न की समस्या हो या तमाम ऐसी योजनाएं हों, खासकर बी.पी.एल. से संबंधित जो कार्डधारक हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। वे रोजाना कमा रहे हैं और रोजना खा रहे हैं। इसलिए उनके लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाये।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कृषि ऋण लिया है, उनका ऋण और ब्याज सरकार माफ करे और जो किसान लगान देते हैं, उनका लगान भी माफ किया जाए। इन इलाकों में किसानों के अलावा जानवरों की स्थिति बहुत बदतर है। वहां जो उनके मवेशी और पक्षी हैं वे भूखों मर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइये, हर तरफ सूखा पड़ रहा है। जहां सूखा है वहां चारा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनके लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I would like to know whether the Government is aware that some districts in Kerala were drought affected. It was reported in the Press that the Kerala Government had made an attempt to impress upon the Central Government in this regard.

I would also like to know whether any Central team had gone there to assess the damage. Will the Government take any action on the basis of their report? Please also let me know whether any Central assistance was given to them. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No, sorry, I will not allow. I had allowed 45 minutes on this question. I myself suggested, at that time, that it is an important issue and that is why I would allow Half-an-Hour Discussion on this question. I cannot violate the rules. I am sorry. Please excuse me.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is very difficult nowadays that the Chair cannot speak and only all of you want to speak. I was

trying to help you.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is because of the ballot, only four hon. Members could be accommodated. They have also referred to their respective States, namely, Bihar, U.P. and Kerala.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please listen to me.

Mr. Minister, I am sure, you are concerned about the whole country. The hon. Members from other different States also wanted to raise their pertinent issues. I am not denying it. But it is not permitted because of the rules. Therefore, I am sure, you will have the whole country in mind while replying.

...(*Interruptions*)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सर, मैं महाराट्र की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सबके लिए कह रहे हैं। हम क्या करेंगे, रूल्स को तोड़ दीजिए, किताब फेंक दीजिए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mohan Rawale, you promised to me that you would behave in a nice manner.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Mohan Rawale, I will put you in the Panel of Chairman. Now, Mr. Minister.

...(*Interruptions*)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया और मैं राजीव जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने यहां सूखे से जूझने वाले दूरगामी मुद्दों को उठाया। मैं दूसरे माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी सम्मान करता हूं। महोदय, आपने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक मैं अपनी बात कुछ शब्दों में रखना चाहता हूं। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि पूरे देश में जहां 70 प्रतिशत से अधिक वर्षा की आपूर्ति जून से सितम्बर में हुई, वह दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर वर्षा निर्भर करती है। इस अवधि में वर्षा की कमी या वर्षा के कुछ सप्ताह में कम या अधिक होने से कृषि पैदावार और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई।

अतः हमारे देश की इन परिस्थितियों के कारण सूखे का संकट देश के किसी न किसी भाग में हर वर्ष मँडराता रहा है किन्तु ऐसा मानना तथ्यों पर आधारित नहीं है कि हमने सूखे को एक अटल सत्य मान लिया है और हमारी नीति सूखा उत्पन्न होने की स्थिति में राहत कार्यों के लिए धन आबंटित करने तक ही सीमित होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखे से निपटने का एकमात्र स्थायी उपाय सिंचाई को सुनिश्चित करना है। सिंचित क्षेत्रों में सम्य-सम्य पर वर्षा के भयंकर अभाव के कारण भयानक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में और ऐसे असिंचित क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक कारणों से सिंचाई के परंपरागत तरीकों को अपनाना संभव नहीं है, क्षेत्रीय विकास की ऐसी प्रणाली बनाई जाती है जिनसे इन क्षेत्रों में सूखे की मार झेलने की क्षमता बढ़ जाए। यदि मैं स्पट शब्दों में कहूँ तो सिंचाई और क्षेत्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रम ही सूखा उन्मूलन के दो उपाय हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शुरू में सन् 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हुई थी, हमारे देश में 32.8 करोड़ हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में 13.1 करोड़ हैक्टेयर भूमि कृषि के अंतर्गत आती थी। इसका केवल 17 प्रतिशत अर्थात् 2.2 करोड़ हैक्टेयर ही सिंचित क्षेत्रों में आता था। अधिक विस्तार में न जाते हुए मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2000 में कृषि के अधीन क्षेत्रफल 13.1 करोड़ हैक्टेयर से बढ़कर 19 करोड़ हैक्टेयर हो गया, जबकि सिंचित क्षेत्र 2.2 करोड़ हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 7.9 करोड़ हैक्टेयर हो गया। अर्थात् सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will get answers on your points.

श्री नीतीश कुमार : आना जाना तो लगा रहता है। हम भी जानते हैं। अभी स्पैसेफिक कंटैक्स्ट में कुछ तो बोलिये। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You always dictate to each other what he will say and what he will not say.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will not allow other hon. Members. मंत्री जी, सूखे के बारे में, फूड फॉर वर्क के बारे में क्या काम कर रहे हैं, वह बताइए।

श्री कांतिलाल भूरिया : थोड़ा सुन लीजिए। नीतीश जी तो मंत्री रहे हैं, आपको मालूम है, पर माननीय सदस्यों को सबको सुनने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, हमको मालूम नहीं है।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, this was a very important matter. I myself suggested at the time when this Question was discussed - on that day, I allowed 45 minutes for one question - that you give a notice for Half-an-Hour Discussion and I shall allow it. Unfortunately, our rules provide for only five hon. Members - one who initiates plus four. I have allowed them. Although only one question is allowed, even then I have allowed Shri Nitish Kumar and other hon. Members because of the importance of the matter.

The hon. Minister has also a right to reply. He must deal with the points you have raised, but if he has a little long preface, you accept it.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, we may be allowed to ask clarifications. ...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होता। आप भी मंत्री बने थे। कैसे रूल तोड़ने के लिए बोलते हैं?

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं राजीव रंजन जी की भावना का सम्मान करते हुए सारी बातें सदन में आपके आदेशानुसार रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हमने आदेश दिया है, आप जल्दी करें।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, यहाँ साधारण सूखा पड़ना बंद हो गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में भी ऐसे पॉकेट हो सकते हैं जिन्हें क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम जैसे वाटर शैड मैनेजमैंट या डीपीएपी जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। उस माध्यम से हम इन सारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। चूँकि सिंचाई का विाय जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है, अतः मैं अधिक आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी मात्र इतना स्पट करना काफी होगा कि राज्यों की पंचवर्ाीय एवं वार्ाकि योजनाओं में इर्रीगेशन को लगभग सभी और विभागों से अधिक धन आबंटित होता है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित ए.आई.बी.पी. कार्यक्रम अर्थात् एक्सीलरेटेड इर्रीगेशन बैनीफिट प्रोग्राम के अन्तर्गत नवम्बर 2004 तक विभिन्न राज्यों में 14,840 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराया गया है। इस राशि का उपयोग राज्यों में 220.76 अरब क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त जल भंडारण संभव हुआ। ये ऐसी उपलब्धियां हैं, जो राज्यों द्वारा अपनी योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों के अतिरिक्त प्राप्त की गई हैं जिनकी वजह से ऐसा संभव हो सका।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्ाा का अभाव अधिक होता है और विशोकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के स्रोत बारहमासी नहीं होते, वहां कुछ ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होती है जिससे उनसे संबंधित क्षेत्रों में सूखे से निपटने की क्षमता बढ़े। इन उपायों से ऐसे असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यकता होती है जहां सूखा बार-बार पड़ता है। उन क्षेत्रों में जहां या तो वित्तीय अभाव के कारण अथवा प्राकृतिक कारणों से भी अभी तक सिंचाई की सुविधा अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। यह उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से पूरा करने की कोशिश की गई है। समय के अभाव के कारण मैं इन कार्यक्रमों का बहुत ही संक्षेप में ब्यौरा देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सूखा प्रबन्धन हो गया, यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में है। â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, please listen to the hon. Minister. मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक-एक बात की जानकारी दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय की मुझ पर कृपा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप चिन्ता न करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो मामला है, उसमें सूखे से निपटने के लिए कई विभागों को मिलाकर â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, please take your seat. The hon. Minister is coming to that point also.

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कई विभागों को मिलाकर सूखे से â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, do not get diverted by the interruptions.

श्री कांतिलाल भूरिया : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डी.पी.ए.पी. अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 182 जिलों में चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से आपकी भावना है, उसी प्रकार से 182 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

SHRI NITISH KUMAR : Sir, he is mentioning only about various schemes. ...(*Interruptions*)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, I have to ask one question, if the hon. Minister agrees.

MR. SPEAKER: No, Mr. Yerrannaidu, I cannot tolerate this. I would not allow it even if he agrees to it.

श्री कांतिलाल भूरिया : इसके अन्तर्गत मार्च 2004 तक 4023.02 करोड़ रुपए की लागत से 107 लाख हैक्टेयर से अधिक सूखे की बार-बार मार झेल रही भूमि को ट्रीट किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मिलित वेस्ट लैंड डैवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत 1559.49 करोड़ रूपए की लागत से 50 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि को ट्रीट किया गया है।

उसी तरह से कृाि मंत्रालय के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के अन्तर्गत, नीतीश कुमार जी को बता रहा हूं कि कृाि मंत्रालय के अन्तर्गत चल रहे राट्रीय वाटरशेड डैवलपमेंट

प्रोजैक्ट जो कि बारानी क्षेत्र के अन्तर्गत 2159.54 करोड़ रुपए की लागत से 75 लाख हैक्टेयर भूमि ट्रीट की जा रही है। उसके साथ इसी मंत्रालय के आर.बी.टी. एंड एफ.टी. आर. कार्यक्रम के अन्तर्गत 54.86 लाख हैक्टेयर भूमि ट्रीट की जा रही है। उसी तरह से मैं संक्षेप में मैं यह कह सकता हूं कि 1950 से लेकर अब तक 5 करोड़ हैक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया गया है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, kindly mention about the short-term measures. आप ही के लिए तो हम बोल रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, 3. 20 करोड़ हैक्टेयर भूमि को वाटरशेड और दूसरी तकनीकों â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Hon. Members' interruptions should not be recorded.

*(Interruptions) â€¦**

श्री कांतिलाल भूरिया : दूसरी तकनीकों से इस प्रकार सिंचित किया गया है कि उनमें सूखे को झेलने की शक्ति बने।

इन क्षेत्रों में मूल्यांकन से यह बात सामने आई कि यहां भूमिगत पानी का स्तर बढ़ा है। ये सब करने से हमारा जलस्तर बढ़ा है और पेड़-पौधों तथा वनस्पति के क्वरेज़ में भी वृद्धि की गई है। हमारी यूपीए सरकार ने एक नया प्रयास किया है। यूपीए सरकार का जो नया प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया जी के मार्गदर्शन में यह प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ड्राइ लैंड फार्मिंग भी शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत किसान के अपने खेत में जल संरक्षण की व्यवस्था का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और योजना आयोग ने सिद्धांत रूप से दसवीं पंचवर्षीय योजना में दो हजार करोड़ रुपए की राशि आबंटन करने का संकेत दिया है ताकि जहां सूखा पड़ रहा है, वहां भूमि के जलस्तर को ऊंचा करके हम किसानों को खुशहाली दिला सकते हैं। इसकी हमारी पूरे सदन को चिन्ता है, उससे उभरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो हजार करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है ताकि किसानों में खुशहाली आए और उनकी तकदीर बदले। इसका एक तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है। इस संक्षिप्त विवरण से यह भी स्पट हो जाता है कि दूरगामी उपायों की अनदेखी नहीं की गई है और संबंधित मंत्रालयों ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I shall conclude this discussion, if it goes in this way because nobody is interested to hear. What is the good of this discussion? Please sit down. You are all senior Members and you know the rules.

...(*Interruptions*)

---

* Not Recorded.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, we want to put a pertinent question. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: When you become a Minister, you would become an articulate Minister.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The interruptions will not be recorded.

*(Interruptions) â€¦**

अध्यक्ष महोदय : यह बात सही नहीं है। आप लोग जानबूझ कर इंटरप्ट कर रहे हैं।

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय राजीव रंजन जी ने जो अपनी बात रखी, उन्होंने सरकार से जानना चाहा, उस बारे में बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। सूखा राहत के लिए बिहार को 162.18 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ-साथ दो लाख मीट्रिक टन अनाज का आबंटन भी कर दिया गया है। इससे अधिक सहायता पर भी फरवरी, 2005 तक विचार किया जाएगा। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। चिन्ता मोहन जी ने भी जानना चाहा है और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जानकारी उपलब्ध कराएंगे और माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। किरण कुमार जी हमारे युवा साथी हैं, वे भी जानकारी चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए 192 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। â€¦ (व्यवधान) सूखा राहत कार्य के लिए भी अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जा रहा है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let there be no running discussion.

श्री कांतिलाल भूरिया : उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी के नालंदा जिले के बारे में भी बता दीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया : नालंदा जिले के बारे में नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने वहां काफी काम किया है। वहां पर और भी काम करने की आवश्यकता है और माननीय सदस्य की भावनाओं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Very good, now you have got the reply.

---

* Not Recorded.

श्री कांतिलाल भूरिया : हम और भी अधिक सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं।

आपने कृ‍ि मंत्री रहते हुए काफी काम कि‍या है, अगर और ‍भी कहीं पर काम करने की ज्‍रूरत होगी तो ‍भी हम प्राथमिकता ‍से काम करेंगे। राधाकृ‍णन जी ‍भी हमारे ‍सीनि‍यर मैम्‍बर हैं, हम उनका ‍सम्‍मान करते हैं। हम उनकी ‍भा‍वना का ‍सम्‍मान करके नि‍श्‍चित ही उनकी ‍भा‍वना के मुता‍बिक काम करने का पूरा प्र‍या‍स करेंगे।

MR. SPEAKER: Thank you hon. Members. I am grateful to you for your kind cooperation.

The House now stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

18.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, December 17, 2004/Agrahayana 26, 1926 (Saka).